सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोनः 0141-2202717
मोः 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-253 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, शनिवार 17 मई , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

राजस्थान में पंचायती राज और निकाय उपचुनाव की तारीखों का एलान

जयपुर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया। यह उपचुनाव 8 जून को होंगे, जबकि मतगणना 9 जून को सुबह 9 बजे से शुरू होगी। पहले ये चुनाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए तनावपूर्ण माहौल के कारण स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन अब नई तारीखों के साथ तैयारियां जोरों पर हैं।

पंचायती राज संस्थानों में जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच के रिक्त पदों पर चुनाव होंगे। आयोग के अनुसार, 1 जून से 31 दिसंबर 2024 तक खाली हुए पदों के लिए यह उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इसमें 1 जिला प्रमुख, 2 प्रधान, 1 उप प्रधान, 7 जिला परिषद सदस्य, 18 पंचायत समिति सदस्य, 17 सरपंच, 15 उप सरपंच और 169 वार्ड पंच

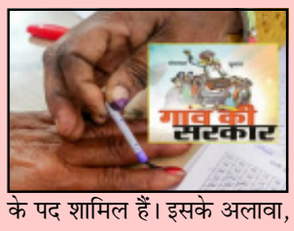

के पद शामिल हैं। इसके अलावा, नगरीय निकायों में 14 निकायों के 12 वार्डों, 1 नगर पालिका अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष के रिक्त पदों पर भी उपचुनाव होगा।

खाली पदों के लिए हो रहे उपचुनाव

उपचुनाव के लिए पंचायती राज संस्थाओं की अधिसूचना 20 मई को और नगरीय निकायों की अधिसूचना 21 मई को जारी होगी। मतदान 8 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इन चुनावों में उन सीटों पर वोटिंग होगी, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2024 में खत्म हो चुका है, लेकिन पद अभी भी खाली हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित क्षेत्रों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीदवार और मतदाता अपनी-अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। पंचायती राज और नगरीय निकायों के ये उपचुनाव स्थानीय स्तर पर नेतृत्व चुनने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। बता दें, यह उपचुनाव राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाली पदों को भरने में अहम होंगे।

उम्मीदवारों के लिए प्रमुख तारीखें-

20 मई- पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी

21 मई- नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना

8 जून- मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक

9 जून- मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू

विपक्ष के बयानों पर जोगाराम पटेल का पलटवार

जयपुर । राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर भारतीय सेना के मनोबल को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां सेना के पराक्रम और देश की अखंडता के खिलाफ नकारात्मक और झूठी बातें फैलाकर गलत काम कर रही हैं। सेना ने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने में अदम्य साहस दिखाया है, जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। पटेल ने विपक्षी नेताओं के हालिया बयानों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा, ऐसे बयान पीड़ित परिवारों के दर्द को और बढ़ाते हैं। पीड़ित परिवारों ने स्वयं बताया है कि आतंकियों ने कायराना हरकत की। यह कहना कि धर्म के आधार पर गोली मारी गई, पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य है। विपक्ष से अपील की कि वे मजहब के नाम पर इस तरह की संवेदनशील घटनाओं को गलत तरीके से पेश न करें। कानून मंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के एक बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कथित तौर पर सेना के एक अधिकारी को जातिसूचक शब्दों से संबोधित किया गया था।

भजनलाल सरकार ने वापस लिया छुट्टियों पर लगी रोक का आदेश

जयपुर। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने एक राहत भरा फैसला लिया है। भारत-पाक सीमा पर तनाव और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद छुट्टियों पर लगी रोक को सरकार ने वापस ले लिया है। अब सभी अधिकारी और कर्मचारी सामान्य प्रक्रिया के तहत अपनी सुविधानुसार छुट्टी ले सकेंगे।

बताते चलें कि 8 मई को राजस्थान सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और सुरक्षा दृष्टिकोण से आपातकालीन तैयारियों को ध्यान में रखते हुए राज्य कर्मचारियों की छुट्टियों पर अस्थायी रोक लगा दी थी। यह निर्णय खासकर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक विभागों के उन कर्मचारियों पर लागू था, जिनकी उपस्थिति हालात को संभालने में आवश्यक मानी गई थी। वहीं, सरकार ने समीक्षा के बाद स्पष्ट किया कि वर्तमान में हालात नियंत्रण में हैं और प्रशासनिक ढांचा सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। ऐसे में कर्मचारियों की निजी, पारिवारिक व स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों की मंजूरी फिर से पूर्ववत कर दी गई है। सरकारी आदेश के बाद राज्यभर के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत से कर्मचारी जिनकी निजी ज़िम्मेदारियां या पहले से नियोजित कार्य प्रभावित हो रहे थे, अब निर्बाध रूप से अवकाश ले सकेंगे। राज्य कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने संवेदनशीलता और समझदारी का परिचय दिया है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर किया हमला

राजस्थान में माफिया राज या कानून का शासन?

जयपुर।जूली ने लिखा कि कागजों में कानून का राज, जमीन पर माफिया का राज, और बताया कि इस हमले में डीएसपी की प्राइवेट बोलेरो को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिसकर्मियों को बनास नदी में छुपना पड़ा और एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई।

राजस्थान में बढ़ते अपराध और पुलिस पर हमलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाईमाधोपुर में खनन माफिया द्वारा पुलिस टीम पर किए गए हमले का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। टीकाराम जूली ने लिखा, कागजों में कानून का राज, जमीन पर माफिया का राज। %हाल-ए-राजस्थान बयां कर रहा है, आए दिन पिटती पुलिस की कहानियां।उन्होंने बताया कि सवाईमाधोपुर में बजरी माफिया

और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। झगड़े के दौरान डीएसपी की प्राइवेट बोलेरो को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए बनास नदी में छुपना पड़ा। इस अफरा-तफरी में एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई।

टीकाराम जूली ने राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछते हुए कहा

प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार खुलेआम क्यों चल रहा है और सरकार चुप क्यों है?

हर दिन कहीं न कहीं पुलिस पिट रही है और माफिया बेखौफ घूम रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन?

क्या राजस्थान में कानून का राज है या माफिया का?

खनन माफिया को खुली छूट क्यों मिल रही है? क्या इसके पीछे सरकार की मिलीभगत है?

डीएसपी की प्राइवेट बोलेरो आखिर किसकी है और उसका वहां क्या काम था?

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा कि प्रदेश जानना चाहता है, क्या सत्ता माफिया से मिली हुई है, या फिर सत्ता चलाने वाले इतने कमजोर हैं?

जयपुर में नशेड़ी के कब्जे से 3 साल की बच्ची बरामद

जयपुर। जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक तीन वर्षीय बच्ची के लापता होने की सूचना से हड़कंप मच गया। बच्ची की तलाश में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज चार घंटे के भीतर उसे सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) तेजस्वनी गौतम (आईपीएस) ने बताया कि 16 मई की रात करीब 12 बजे नाहर सिंह नामक व्यक्ति, जो वर्तमान में सेक्टर 11, मालवीयनगर में किरायेदार के रूप में रह रहा है, ने थाना जवाहर सर्किल में रिपोर्ट दी कि उसकी तीन साल की बेटी सेक्टर 13 की सब्जी मंडी में खेलते हुए लापता हो गई है।

नाहर सिंह का कहना था कि वह सब्जी मंडी में ठेला लगाता है और उसी दौरान उसकी बेटी वहीं पास में खेल रही थी। कुछ देर बाद उसने देखा तो बच्ची नजर नहीं आई। आसपास काफी तलाश करने के बावजूद बच्ची का कुछ पता नहीं चला। सूचना मिलते ही थानाधिकारी मदनलाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर प्रथम, और सहायक पुलिस आयुक्त मालवीय नगर सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे।

बच्ची की तलाश के लिए अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया और आसपास के सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट कर दिया गया। रात का समय होने की वजह से दुकानों और घरों के बंद होने से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने में परेशानी आई, लेकिन आम जनता की मदद लेकर दुकानों के मालिकों को उनके घरों से बुलाया गया और फुटेज खंगाले गए। तभी एक वीडियो में एक संदिग्ध व्यक्ति बच्ची को उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया, जो नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ नजर आया।

फुटेज के आधार पर तलाशी अभियान तेज किया गया। उसी दौरान एक व्यक्ति एक गली में अकेला आता हुआ दिखा, जो आगे जाकर बंद हो रही थी। पुलिस ने उस गली के सभी मकानों की तलाशी ली। एक मकान में कुछ बंगाली मजदूर रह रहे थे, जिनसे पूछताछ करने पर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान अशोक कुमार बर्मन के रूप में हुई। वह पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले का निवासी है और मजदूरी करता है। उसकी हुलिए से पुष्टि के बाद सेक्टर 7 मालवीयनगर में स्थित एक मकान पर दबिश दी गई, जहां वह बच्ची के साथ एक कमरे में सोता हुआ मिला। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया और आरोपी अशोक बर्मन को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। जयपुर पुलिस की सक्रियता, जनता के सहयोग और अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से एक बड़ी अनहोनी टल गई और बच्ची को सुरक्षित वापस लाया जा सका।

100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों से 50 करोड़ की ठगी, सरकारी टीचर गिरफ्तार; कांस्टेबल भाई अब भी फरार

अजमेर। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि शिकायत मिलते ही कांस्टेबल पवन मीणा को 25 दिन पहले ही निलंबित कर दिया गया। दोनों भाइयों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। फिलहाल पुलिस फरार चल रहे पवन की तलाश में जुटी है।

राजस्थान के अजमेर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो सगे भाइयों ने करोड़पति बनने का सपना दिखाकर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों से करीब 50 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों में एक आरोपी सरकारी स्कूल में शिक्षक है और दूसरा पुलिस कांस्टेबल, जो इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है।

पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर आरोपी सरकारी शिक्षक कुलदीप मीणा (34) को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई और मुख्य साजिशकर्ता पुलिस कांस्टेबल पवन मीणा अब भी फरार है। कुलदीप को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वह लगातार हुलिया और ठिकाना बदलकर बचता रहा। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित

किया गया था।क्लॉक टॉवर थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कुलदीप को गिरफ्तार किया गया। उसके बैंक खाते से करीब 18 लाख रुपये की राशि भी बरामद की गई है। उसे कोर्ट में पेश कर पांच दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचा जा सके।

पुलिसकर्मियों को चौगुना मुनाफा देने का लालच

इस हाई-प्रोफाइल ठगी का पर्दाफाश तब हुआ जब मदनगंज-किशनगढ़ में तैनात कांस्टेबल दीपक वैष्णव ने क्लॉक टॉवर थाने में मामला दर्ज करवाया। शिकायत में उसने बताया कि उसका बैचमेट पवन मीणा अक्सर थानों में आकर %बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश और %चौगुनी कमाई का झांसा दिया करता था। पवन और उसके भाई कुलदीप ने मिलकर एक फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई, जिसके तहत उन्होंने दावा किया कि निवेशकों का पैसा नेशनल हाईवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। इस भरोसे के जाल में आकर कई पुलिसकर्मियों ने अपनी मेहनत की कमाई इस स्कीम में लगा दी।

वर्दी और नेटवर्क का इस्तेमाल कर रची ठगी की बड़ी साजिश

एसपी वंदिता राणा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत मिलते ही कांस्टेबल पवन मीणा को 25 दिन पहले ही निलंबित कर दिया गया। दोनों भाइयों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। फिलहाल पुलिस फरार चल रहे पवन की तलाश में जुटी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह ठगी योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। पवन मीणा ने न सिर्फ अपनी वर्दी और पद का दुरुपयोग किया, बल्कि पुलिस विभाग के भीतर अपने नेटवर्क के जरिए आसानी से अन्य पुलिसकर्मियों को भरोसे में लिया और बड़ी राशि हड़प ली।

इस घटना ने पुलिस विभाग के आंतरिक तंत्र और भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब बाकी निवेशकों की सूची तैयार कर रही है ताकि इस घोटाले की वास्तविक रकम और पीड़ितों की संख्या का सटीक अनुमान लगाया जा सके। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल था।

प्रदीप मिश्रा की कथा के बाद चली गई युवक की जान, आयोजकों पर केस दर्ज

जयपुर। हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों में आक्रोश फैल गया और आयोजकों अनिल संत व राजन शर्मा के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ताओं ने धार्मिक आयोजन के नाम पर चंदे में आर्थिक गड़बड़ी और धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए हैं।

जयपुर के विद्याधर नगर में आयोजित सात दिवसीय शिव महापुराण कथा कार्यक्रम के बाद एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। कथास्थल पर लटकती रस्सियों में उलझकर एक श्रमिक की जान चली गई। इस घटना के बाद आयोजकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा एक से 7 मई तक विद्याधर नगर में आयोजित की गई थी। आयोजन

के बाद अस्थायी ढांचा और रस्सियां समय पर नहीं हटाई गईं। 8 मई को दिनेश नामक श्रमिक जब अपनी बाइक से उस मार्ग से गुजर रहा था, तभी लटकती रस्सियों में उलझकर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस हादसे से इलाके में गहरा आक्रोश फैल गया। स्थानीय नागरिकों ने इसे आयोजन समिति की घोर लापरवाही बताया। विद्याधर नगर थाने में आयोजकों अनिल संत और राजन शर्मा के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 105 (पूर्व में धारा 304), 118(1) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत बलराम जाखड़, महेश मावलिया, नरेंद्र चौधरी और भवानी सिंह शेखावत द्वारा दी गई।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कथा के नाम पर करोड़ों रुपये का चंदा इकट्ठा किया गया, लेकिन उसका कोई हिसाब-किताब नहीं दिया गया।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने स्वयं 1.51 लाख नकद दान दिया, लेकिन आयोजकों ने कोई रसीद नहीं दी। धार्मिक आयोजन की आड़ में धोखाधड़ी और आर्थिक गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं। एफआईआर में नामजद अनिल संत पर पहले से भी कई जमीन घोटालों और धोखाधड़ी के आरोप हैं। उन्हें भूमाफिया बताया गया है और वर्तमान में उन पर कुछ मामलों की जांच जारी है।

सहज, सरल मनोज माथुर हमेशा याद रहेंगे-देवनानी

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के सहज, सरल व्यक्तित्व के धनी मनोज माथुर जैसे जागरूक पत्रकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका असमय चले जाना हम सभी मित्रगण, पत्रकार और पारिवारिक सदस्यों के लिए बहुत कष्टकारी है। मनोज माथुर के आदर्शों के अनुरूप पत्रकार आगे बढ़े, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माथुर के लिए पत्रकारिता जीवन का आधार थी। देवनानी शुक्रवार को यहां नारायण सिंह सर्किल स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब के सभागार में मनोज माथुर फाउण्डेशन द्वारा आयोजित मनोज माथुर अवार्ड समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। देवनानी ने दीप प्रज्ज्वलन कर समारोह का शुभारम्भ किया। देवनानी ने मनोज माथुर फाउण्डेशन को एक लाख रुपये धनराशि उनकी ओर से दिये जाने की घोषणा की। समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का संदेश भी पढ़कर सुनाया

गया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रदान किये गये अवार्ड पुरस्कारों की सराहना की। समारोह में मनोज माथुर के जीवन पर आधारित वृत्त चित्र दिखाया गया।

समारोह में देवनानी ने प्रिन्ट मीडिया में अवधेश आकोदिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महेश दाधीच और डिजिटल मीडिया में सौरभ भटट को मनोज माथुर अवार्ड प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी थे। स्व. मनोज माथुर की पत्नी सुलक्षणा माथुर ने अतिथिगण और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का पौधा भेंट कर अभिनन्दन किया।

देवनानी ने कहा कि पत्रकारों की भूमिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है। पत्रकार जगत से जुडे हुए उन्हें भी 50 वर्षों से अधिक समय हो गया है। पत्रकार जगत सकारात्मक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की आजादी के समय भी पत्रकार जगत ने राष्ट्र में देश भक्ति की को जगाये रखा। उन्होंने कहा कि नारद पत्रकारिता के जनक थे। वे संवाद के संवाहक थे। श्री देवनानी ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर मिशन को पत्रकारों ने राष्ट्रवाद की भावना के अनुरूप प्रसारित किया, यह अभिन्दनीय है। देवनानी ने कहा कि आज भारत की विश्व में विशेष पहचान बनी है। भारत को बढ़ता हुआ अन्य देश नहीं देख पा रहे है। अन्य देशों की नजरों में भारत के प्रति खटखटाहट ही हमारे देश की ताकत है। नये भारत को श्रेष्ठ बनाने और उसे निरन्तर आगे बढ़ाने में सभी सक्रिय भागीदारी निभाएं। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। देवनानी ने कहा कि लोकतंत्र में विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विधान सभा में नवीनता लाने के लिए श्रेष्ठ परिवर्तन करने का वे निरन्तर प्रयास कर रहे है। देवनानी ने इसके लिए पत्रकारों से सकारात्मक परामर्श देने के लिए कहा।

अरुणाचली चाल है पाक के हक में चीन की बौखलाहट

चीन अपनी दोगली नीति, षडयंत्रकारी हरकतों एवं विस्तारवादी मंशा से कभी बाज नहीं आता। वह हमेशा कोई ऐसी कुचेष्टा करता ही रहता है जिससे भारत चीन बॉर्डर पर अक्सर तनाव रहता है। हालांकि भारत ने दो टूक जवाब देते हुए साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और यह चीनी दुष्प्रचार के सिवाय कुछ नहीं है। चीन की इस हरकत ने यह साफ कर दिया है कि उससे संबंध सुधारने की भारत की तरफ से कितनी ही पहल हो जाए, वह सुधरने वाला नहीं ह

(लेखक - ललित गर्ग/)

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सफल 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद चीन बौखला गया है। पाकिस्तान की करारी हार एवं उसे दिये गये सबक को चीन पचा नहीं पा रहा है। चीन-पाक की सदाबहार दोस्ती के उदाहरण बार-बार सामने आते रहे हैं, हाल ही में सैन्य टकराव के दौरान चीन ने प्रत्यक्ष व परोक्ष तौर पर पाकिस्तान का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि सैन्य व आर्थिक मदद भी की। ऐसे ही संवेदनशील समय पर चीन ने भारतीय जमीन पर दावेदारी जताने एवं अरुणाचल के 27 स्थानों को चीनी नाम देने की कुचेष्टा की है। उसकी यह नापाक कोशिश भी पाक के साथ खड़े होने का ही प्रयास है। यह ध्यान रहे कि वह अरुणाचल एवं उसके अनेक क्षेत्रों, इनमें आवासीय क्षेत्रों के साथ पहाड़ और नदियां भी हैं, इनको पहले ही चीनी नाम दे चुका है। भारत सरकार ने अरुणाचल के भीतरी स्थानों को नए नाम देने के चीन के निराधार और बेतुके प्रयासों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए इसकी निन्दा की है। चीन अपनी दोगली नीति, षडयंत्रकारी हरकतों एवं विस्तारवादी मंशा से कभी बाज नहीं आता। वह हमेशा कोई ऐसी कुचेष्टा करता ही रहता है जिससे भारत चीन बॉर्डर पर अक्सर तनाव रहता है। हालांकि भारत ने दो टूक जवाब देते हुए साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और यह चीनी दुष्प्रचार के सिवाय कुछ नहीं है। चीन की इस हरकत ने यह साफ कर दिया है कि उससे संबंध सुधारने की भारत की तरफ से कितनी ही पहल हो जाए, वह सुधरने वाला नहीं है।

निश्चित ही चीन की ये दकियानूसी हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं, यह उसके दुस्साहस एवं उच्छृंखलता का द्योतक है। नाम बदलने से इस स्पष्ट और निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। इस तरह की करतूतों, बचकानी एवं बेतूकी हरकतों से भारत को उकसाना चाहता है। इसी नीति के तहत वह भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पैठ बना कर पुलों, सड़कों, व्यावसायिक केंद्रों आदि का निर्माण कर भारत की सीमा पर तनाव पैदा करने की भी कोशिश करता रहा है। शायद उसने यह मुगालता पाल लिया है कि ताजा घटनाक्रम से भारत दबाव में आ जाएगा लेकिन भारत अब ऐसे किसी दबाव में न तो आयेगा, बल्कि इनका सक्षम एवं तीक्ष्ण तरीके से जबाव देने में भारत सक्षम है। चीन का अधिक बौखलाहट एवं खीज का बड़ा कारण भारत ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल आदि की इस कदर पोल खोल कर रख दी कि अब उसके लिए दुनिया के निर्धन देशों को अपने दोयम दर्जे एवं घटिसा किस्म के चीनी हथियार बेचना कठिन होगा। पाकिस्तान ने जिस चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया था, उसे भारत ने नाकाम कर दिया।

चीन यह तो चाहता है कि भारत उसके हितों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरते, लेकिन खुद उसकी ओर से भारत के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता को लगातार नजरअंदाज करता है। चीन भरोसे लायक देश नहीं है, चीन के प्रति कठोर रवैया जरूरी है। निस्संदेह नाम बदलने जैसी घटनाएं हमें सतर्क करती हैं कि चीन के साथ मैत्री संबंधों के निर्धारण के दौरान हमें सजग, सावधान व सचेत रहना चाहिए। अन्यथा चीन पीठ पर वार करने से नहीं चूकने वाला है। भारत को चीन के साथ अपनी तिब्बत नीति पर भी नए सिरे से विचार करना होगा। पिछले तीसरे साल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अनेक स्थानों के नाम बदले हैं। चीन अरुणाचल को जांगनान के नाम से दर्शाता है। वहीं इसे तिब्बत के दक्षिणी हिस्से के रूप में होने का दावा करता है। चीन किये गये वायदों एवं समझौतों से पीछे हटता रहा है, चीनी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच 1993, 1996, 2005 और 2013 में परस्पर भरोसा पैदा करने वाले समझौतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को भारतीय दावे वाले इलाकों में अतिक्रमण करने का आदेश दिया। इसी का अंजाम रही जून 2020 में गलवान घाटी जैसी घटना। जिसमें उसके सैनिक गलवान घाटी में घुस आए थे, जिन्हें रोकने में खूनी संघर्ष हुआ। तबसे दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने के इरादे से वह चोरी-छिपे और चालबाजी से घुसपैठ करने की कोशिशें करता रहता है। चीन की विस्तारवादी नीति भारत सहित सम्पूर्ण एशिया के लिये ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बड़ा खतरा है।

चीन भारत की बढ़ती ताकत एवं रूतबे से परेशान है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत चीन को चुभती रही है, इसलिए वह चोरी, चालाकी और चालबाजी से भारत को कमजोर करने की चालें चलता रहता है। दरअसल, सीमाओं को लेकर नित नए विवादास्पद तथ्य लाना चीन की फितरत में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, अक्साई चिन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर पर भी चीन अपना दावा जताता रहा है। शातिर और चालबाज चीन अरुणाचल के किसी दस्तावेज पर भारत का नाम स्वीकार नहीं करता। कुछ मौकों पर तो वह अरुणाचल को अपने नक्शे में शामिल कर दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश कर चुका है कि वह उसका इलाका है। मगर भारत की तरफ से मिले सख्त प्रतिरोध की वजह, सामरिक शक्ति और रणनीतिक सूझ-बूझ से उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है।

भारत को अनेक मोर्चों पर चीन को आडे हाथ लेना होगा, सबसे जरूरी है चीन सामान का बहिष्कार, इस पर सरकार के साथ हमारे उद्योग जगत एवं आम जनता को भी गंभीरता से सोचना होगा। ऐसा करके ही चीन की कमर को तोड़ा जा सकता है, आज दुनिया के अनेक देश चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, हमें भी कठोर कदम उठाने होंगे। भारत ने जब भी पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकियों को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में डलवाने का प्रयास किया, चीन संयुक्त राष्ट्र में अपने वीटो का प्रयोग कर उसे रोकने की कोशिश करता रहा है, जबकि पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का समर्थन करती रही है। जिससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने तथा व्यापार-कारोबार बढ़ाने की बात करने वाला चीन भारत के प्रति कैसी दुर्भावना रखता है। वह वैश्विक संगठनों व मंचों पर भारत के साथ खड़ा होने का दावा एवं ढोंग ही करता है।

भारत एवं चीन दोनों देशों के बीच संबंधों में आने वाली तल्खी की बड़ी वजह भी चीन की नीयत में खोट, उच्छृंखलता एवं अनुशासनहीनता ही है। चीन ने एक बार फिर अपनी इस हरकत से भारत के प्रति शत्रुता को ही जाहिर किया है। भारत के साथ चीन का बर्ताव हमेशा दोगला एवं द्वेषपूर्ण रहा है। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि चीन किस तरह पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल करता रहा है। जाहिर बात है कि चीन ने ऐसा न केवल चुनौतीपूर्ण समय में भारत का ध्यान भटकाने के लिये किया है, बल्कि पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिये भी किया है। अपनी आर्थिक शक्ति के नशे में चूर अहंकारी चीन अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों को जिस तरह धता बता रहा है, उससे वह विश्व व्यवस्था के लिए खतरा ही बन रहा है। अब यह भी किसी से छिपा नहीं कि वह गरीब देशों को किस तरह कर्ज के जाल में फंसाकर उनका शोषण कर रहा है। चीन भूल गया है कि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है और आज का भारत चीन को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। भारत की रणनीति साफ है, स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश होती है तो जवाब भी उतना ही प्रचंड देने में वह समर्थ हैं। भारतीय सेना में सरहदें बदल देने की क्षमता है, दुश्मनों को इरादों को ध्वस्त करने का मादा है इसलिये चीन अपने नक्शे में भले ही छेड़छाड़ करता रहे, लेकिन भारत की भूमि पर कब्जाने की उसकी मंशा अब कभी साकार नहीं होगी। प्रेषक:

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

नफरती बोल

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की बहादुर सेना ने जब पाक को सबक सिखा, देश को गौरव का अहसास कराया तब नफरती ट्रोल सेना, नीचता की सीमा तक गिरती नजर आई। जिसके विरोध में देश में तीखे गुस्से की लहर देखी गयी। इस बिगड़ैल ट्रोल सेना ने ऑनलाइन गाली-गलौज करने में किसी को भी नहीं बख्शा। यहां तक कि सादगी के व्यक्तित्व व गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति वाले विदेश सचिव विक्रम मिसरी तक को नहीं छोड़ा। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा भी निशाने पर आए। यहां तक कि पहलगाम हमले में विधवा हुई हिमांशी नरवाल को भी नहीं बख्शा गया। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने और पहलगाम की घटना के बाद कश्मीरियों को निशाने पर न लेने का आह्वान किया था। निश्चित रूप से यह देश में सामाजिक समरसता के लिये वक्त की आवाज भी थी। लेकिन सबसे परेशान करने वाली घटना वह थी, जिसमें भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने बेसिर-पैर का सांप्रदायिक सोच वाला बयान दिया। दरअसल, इस सप्ताह की शुरुआत में मंत्री विजय शाह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की प्रेस ब्रीफ देने वाली कर्नल सोफिया के बारे में चौंकाने वाली सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। निश्चय ही देश के लिये महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला सैन्य अधिकारी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। मंत्री ने असंगत रूप से पहलगाम में आतंक फैलाने वाले आतंकवादियों से दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से साम्य दर्शाने का कुत्सित प्रयास किया। हालांकि यह टिप्पणी सोमवार को की गई थी, लेकिन मंत्री शाह के खिलाफ प्राथमिकी मुश्किल से बुधवार रात दर्ज की गई। वह भी शासन द्वारा स्वत- संज्ञान लेने के बजाय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ही दर्ज की गई। हाईकोर्ट ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ 'गटर की भाषा' इस्तेमाल करने के लिए मंत्री शाह को फटकार लगायी। सही मायनों में हाईकोर्ट ने न केवल मंत्री को आईना दिखाया बल्कि तमाम बेलगाम बयानबाजी करने वालों को भी सख्त संदेश दिया। उल्लेखनीय है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जब आरोपी मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से राहत के लिये गुहार लगायी तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आड़े हाथ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को चेतावनी दी कि एक मंत्री को ऐसे समय में जिम्मेदारी की भावना के साथ बोलना चाहिए, जब देश चुनौतिपूर्ण स्थिति से गुजर रहा हो। फिर कोर्ट की सख्ती के बाद शाह ने खेद व्यक्त किया। उन्होंने फिर सफाई दी कि वह कर्नल कुरैशी का अपनी बहन से ज्यादा सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं लौटता है, उसी तरह उनकी अनर्गल बयानबाजी से जो नुकसान हो चुका था, उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। इससे बड़ी विसंगति यह भी कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की तात्कालिक गंभीर पहल नहीं की। यह विडंबना ही है कि पार्टी नेतृत्व इंतजार का खेल खेल रहा है। वहीं दूसरी ओर आरोपी मंत्री अपने बचाव के लिये कानूनी विकल्पों को आजमाने में व्यस्त रहा है। दरअसल, भाजपा की राजनीतिक मजबूरी यह है कि जातीय समीकरणों के हिसाब से वे पार्टी के लिये महत्वपूर्ण हैं। वे उस राज्य में आदिवासी कल्याण मंत्री हैं जहां अनुसूचित जनजातियों की आबादी का पांचवां हिस्सा मौजूद है।

विभाजन की ओर बढ़ता पाकिस्तान?

(लेखक - सुरेश हिंदुस्तानी)

पाकिस्तान की ओर से भारत के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद आखिरकार युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या आतंक को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है, क्योंकि पूर्व में ऐसा कहने के बाद भी हर बार पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में आतंकी घटनाएं की जाती रही हैं। पहलगांव की घटना में आतंकवादियों ने निर्दोष 26 हिन्दु पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पस्त हो गया। पाकिस्तान सरकार की ओर से युद्ध विराम के बारे में कहा गया कि इस समय पाकिस्तान को बचाने की जरूरत है। इस कथन का बहुत ही स्पष्ट आशय यह भी निकाला जा सकता है कि अगर युद्ध जारी रहता तो पाकिस्तान नाम का देश इस धरती पर नहीं रहता। इसलिए पाकिस्तान ने अपने देश को बचाने के लिए ही यह रास्ता चुना। अमेरिका ने इस मामले में दखल देते हुए दोनों देशों के बीच सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की ओर से हमेशा यही कहा गया कि भारत आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अपना अभियान चला रहा है। इस मामले में विश्व के अधिकांश देश भारत के साथ खड़े होते दिखाई दिए, वहीं पाकिस्तान अकेला हो गया था। इससे पाकिस्तान निराश हो गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी माना जा सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर ग्रे सूची में आने का खतरा बढ़ता जा रहा था। एफएटीएफ की ओर से पाकिस्तान का ऐसी चेतावनी भी दे दी गई थी। अगर पाकिस्तान ग्रे सूची में आता तो उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लग सकते थे, जो पाकिस्तान के हित में नहीं होते। युद्ध विराम का एक बड़ा यह भी हो सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से बदहाल हो चुके पाकिस्तान को अब कर्ज भी मिल सकता है। जिसकी उसे बहुत आवश्यकता है।

अब पाकिस्तान, भारत की जवाबी कार्यवाही से बच गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही अंदर जो लावा सुलग रहा है। पाकिस्तान की सरकार को उससे बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान ब्लूचिस्तान ने अपनी आजादी की लड़ाई को जारी रखते हुए पाकिस्तान की सेना को अपना निशाना बनाया। यानी पाकिस्तान एक तरफ भारत से लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर उसे अपने ही देश में ब्लूचिस्तान की ओर से कड़ी चुनौती मिल रही थी। पाकिस्तान का आरोप था कि ब्लूचिस्तान को भारत भड़का रहा है। इसे इसलिए भी सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्लूचिस्तान ऐसी लड़ाई लम्बे समय से लड़ रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही बीएलए के सैनिकों ने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक करके पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अब यही कहा जा सकता है कि ब्लूचिस्तान शायद ही पाकिस्तान में रहे। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान विभाजन के रास्ते पर चल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है। कई विशेषज्ञ यह दावा भी करते दिख रहे हैं कि पाकिस्तान चार टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। यह इसलिए भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर यही स्थिति बन रही है।

वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने ही देश की जनता के निशाने पर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना और सेना के साथ कदम मिलाने वाले आतंकी संगठन सरकार के युद्ध विराम वाले निर्णय से नाखुश हैं। इसका परिणाम क्या होगा, यह तो आने वाला समय ही बताने में समर्थ होगा। लेकिन यह पाकिस्तान की वास्तविकता है कि युद्ध जैसी स्थिति बनने के बाद सेना और आतंकियों ने सरकार के समक्ष गंभीर संकट पैदा किया है। यहां तक कि सेना ने सरकार को अपदस्थ करके खुद सत्ता का संचालन किया है। दूसरी बात यह भी है कि जंग के हालात पैदान करने के लिए पाकिस्तान की जनता सरकार और सेना प्रमुख को ही पूरी तरह से दोषी बता रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पहलगांव की घटना से तीन दिन पूर्व कहा था कि हिन्दू और मुसलमान एक साथ कभी नहीं रह सकते। इसके साथ ही यह भी कहा कि भारत का कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। सेना प्रमुख का यह बयान मुसलमानों को भड़काने जैसा ही था। इसलिए पहलगांव की घटना को इसी बयान की प्रतिक्रिया स्वरूप माना जा रहा है।

पहलगांव की आतंकी घटना के बाद भारत की ओर से आपरेशन सिन्दूर चलाकर पाकिस्तान स्थिति आतंकी शिविरों को नष्ट करके पाकिस्तान के आक्रमण की योजना को असफल कर दिया। भारत की ओर की गई जवाबी कार्रवाई में सौ से ज्यादा आतंकी मारे गए। यह पाकिस्तान के लिए जबरदस्त आघात ही था, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और सेना इन्हीं आतंकियों की दम पर भारत को आंखें दिखा रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान के हर आक्रमण को भारत ने असफल कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान बेदम सा होता चला गया। अब हालांकि युद्ध विराम हो गया है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है। विश्वास करना इसलिए भी कठिन सा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकी शिविर चल रहे हैं, उनमें केवल और केवल भारत के विरोध में नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। यह नफरती फौज भविष्य में भारत में आतंक फैलाने के लिए ही तैयार की जा रही है। पाकिस्तान अगर वास्तव में ही युद्ध विराम को लागू करना चाहता है तो उसे पाकिस्तान में चल रहे आतंकी शिविरों को समाप्त करना होगा। जब तक पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। तब तक उस पर विश्वास करना कठिन ही है। खैर... कुछ भी हो, पाकिस्तान अंदर से तो टूट ही रहा है, अब युद्ध विराम के बाद वहां की सरकार, सेना और जनता अलग अलग राग अलाप रहे हैं। इसकी परिणति पाकिस्तान के लिए खतरनाक भी हो सकती है।

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

(चिंतन-मनन)

आत्मज्ञान के लिए पात्रता

एक बार की बात है। एक धनिक सेठ एक पहुंचे हुए संत के पास पहुंचा और उनसे बोला, महाराज, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना का प्रयास करता हूं। परंतु मेरा मन ध्यान में एकाग्र ही नहीं हो पाता। आप मुझे मेरे मन को एकाग्र करने का कोई मंत्र बताएं। धनिक सेठ की बात सुनकर संत बोले, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वहां पर तुम्हें एकाग्रता का मंत्र प्रदान करूंगा। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ कि एक पहुंचे हुए संत उसके घर पधारेंगे। उसने अपनी हवेली की सफाई करवाई और संत के लिए अच्छे-अच्छे पकवान तैयार करवाए। नियत समय पर संत उसकी हवेली पर पधारे। सेठ ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। सेठ की पत्नी ने मेवों व शुद्ध घी से स्वादिष्ट हलवा तैयार किया था। चांदी के पात्र में हलवा सजाकर संत को दिया गया तो संत ने फौरन अपना कमंडल आगे कर दिया और बोले, यह हलवा इस कमंडल में डाल दो। सेठ ने देखा कि कमंडल में पहले ही कूड़ा-करकट भरा हुआ है। यह देखकर वह बोला, महाराज, यह हलवा मैं इसमें कैसे डाल सकता हूं। कमंडल में तो कूड़ा-करकट भरा हुआ है। इसमें हलवा डालने पर भला वह खाने योग्य कहां रह जाएगा, अपितु वह भी कूड़े-करकट के साथ मिलकर दूषित हो जाएगा। यह सुनकर संत मुस्कराते हुए बोले, वत्स, तुम ठीक कहते हो। सबसे पहले पात्रता विकसित करो, तभी तो आत्मज्ञान के योग्य बन पाओगे। यदि मन-मस्तिष्क में विकार तथा कुसंस्कार भरे हैं, तो वे आत्मज्ञान को आत्मसात कैसे कर पाएंगे? एकाग्रता भी तभी बनती है, जब व्यक्ति शुद्धता से कार्य करने का संकल्प करता है। संत की बातें सुनकर धनिक सेठ ने उसी समय संकल्प लिया कि वह शुद्ध आचरण से तथा परोपकार के द्वारा पहले अपने को सुपात्र बनाएगा, ताकि उसे आत्मज्ञान सहजता से प्राप्त हो सके।

विचार मंथन

राफेल एक बार फिर चर्चाओं में

(लेखक-सनत जैन)

फ्रांस का राफेल विमान एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद को लेकर सीज फायर होने के बाद राफेल विमान की गुणवत्ता और फ्रांस का भारत के साथ सहयोग ना करना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं का विषय बन गया है। भारत और फ्रांस के बीच हुई राफेल डील को एक समय पर भारत की सबसे बड़ी सामरिक मजबूती के रूप में प्रचारित किया गया था। हालिया घटनाक्रम और युद्ध के अनुभवों ने राफेल विमान में भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में जो डील हुई है, उस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से भारत ने राफेल और मरीन राफेल विमान खरीदने का सौदा फ्रांस से किया है। इसके बावजूद भारत को सोर्स कोड जैसी महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी फ्रांस द्वारा भारत सरकार को नहीं दी जा रही है। फ्रांस की सरकार ने भारत सरकार को सोर्स कोड नहीं दिया। जिसके कारण नौ सेना के विमानों को अपग्रेड करने के जो परिणाम भारतीय सेना को मिलने थे, वह नहीं मिले। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स कोड विमान की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है।

सोर्स कोड नही मिलने की वजह से भारत स्वदेशी मिसाइलों को राफेल से सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकता है। जिससे युद्ध की स्थिति में समय, संसाधन और रणनीतिक लाभ भारतीय सेना को नहीं मिले, जो मिल सकते थे। यही गलती भारत सरकार ने मिराज 2000 की खरीद के समय भी की थी, जब फ्रांस ने कोड एक्सेस देने से इनकार कर दिया था। भारत को हर बार सिस्टम अपग्रेड के लिए फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ता है। जिससे भारतीय सेना समय आने पर मुकाबले में पिछड़ जाती है। भारतीय सेना को हमेशा फ्रांस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। भारत सरकार को समय-समय पर बहुत सारा धन भी खर्च करना पड़ता है। फ्रांस की कथनी और करनी में अंतर सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में फ्रांस ने भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन टीआरएफ के पक्ष में मतदान किया है। फ्रांस ने भारत को ऐसे समय पर धोखा दिया है। जब भारत को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत सरकार ने काफी महंगी कीमत में राफेल की विमान खरीदे हैं। पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए हमले मे राफेल विमान को लेकर तरह-तरह की खबरें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ रही हैं। कहा जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध में राफेल विमान का प्रदर्शन ठीक नहीं था। यह कहा जा रहा है, राफेल का एक विमान पाकिस्तान की सेना के विमान द्वारा गिरा दिया गया है। राफेल कंपनी के शेयर भी इस खबर के बाद 10 फ़ीसदी से ज्यादा गिर गए हैं। राफेल विमान को लेकर एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा कारणों से सरकार द्वारा राफेल सौदे के संबंध में लिफाफे में बंद जानकारी दी, जो आज भी लिफाफे में बंद है। ऐसी स्थिति में फ्रांस और राफेल को लेकर एक बार फिर विवाद राजनीतिक मुद्दा बनने लगा है। राफेल को लेकर अभी तक भारत सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। दुनिया भर के अखबारों में राफेल विमान को लेकर जो बातें लिखी जा रही हैं, और जो बातें सामने आ रही हैं। उससे निश्चित रूप से जहां सरकार की मुश्किलें बढ़ेगी। वहीं भारतीय सेना पर राफेल की तुलना में और बेहतर तकनीकी के विमान खरीदने का दबाव बन गया है। भारत के सीमावर्ती देशों के साथ संबंध मधुर नहीं रहे। हाल ही के पाकिस्तान के साथ हुए हमले में जिस तरह से पाकिस्तान को अमेरिका और चीन जैसी महाशक्ति का समर्थन मिला है। इस लड़ाई में भारत अलग-थलग पड़ गया है। सरकार और भारतीय वायुसेना को इस समय सजग रहने की जरूरत है। सुरक्षा कारणों से भले सरकार सेना की जानकारी सार्वजनिक ना कर रही हो।

सेना को मजबूत बनाने और फ्रांस के साथ रिश्तो को लेकर भारत सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है। आगे जो भी रक्षा सौदे सरकार करें, उसमें तकनीकी और सोर्स कोड को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

पाकिस्तान एयर डिफेंस को तबाह करने भारत ने दागी 15 ब्रह्मोस मिसाइलें

निशाना इतना सटीक पाकिस्तान को भारी सैन्य नुकसान हुआ

नई दिल्ली।

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की एयर डिफेंस को पंगु बनाने के लिए करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागीं। भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की कार्रवाई से असीम मुनीर की पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया। क्योंकि, इस हमले में पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस तबाह हो गए। भारत ने इसके पहले पाकिस्तान के रडारों को उकसाने और निष्क्रिय करने के लिए पायलट रहित ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात को भारत में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की थी। इसी के जवाब में भारत ने कार्रवाई की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल की सलाह पर ब्रह्मोस मिसाइल को मिशन में मुख्य हथियार के रूप में चुना गया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात को जो श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और भुज में कई सैन्य और रिहायशी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी खतरों को नाकाम कर दिया था। इसके जबाव में भारतीय सशस्त्र बलों ने अगली सुबह पाकिस्तान पर तालमेल के साथ बहुत ही सटीक और घातक हमले किए। उन्होंने लाहौर स्थित दुश्मन के एक रडार सहित पाकिस्तानी एयर डिफेंस रडारों को निशाना बनाया। 9-10 मई की रात को वायुसेना ने पाकिस्तानी वायु सेना के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला करके अपनी जवाबी कार्रवाई और तेज कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि वायुसेना ने पाकिस्तानी रडारों और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करने के लिए पहला बिना पायलट वाले विमानों का इस्तेमाल किया। एक बार जब पाकिस्तानी रडार और एयर डिफेंस सक्रिय हो गए, तब भारत ने उन्हें हारोप कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को डीएक्टिवेट करके तबाह किया। इस कदम के साथ ही ब्रह्मोस और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करके आगे के मिसाइल हमलों का रास्ता साफ हो गया। इन मिसाइलों को ले जाने वाले फाइटर जेट्स ने भारत के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के विभिन्न ठिकानों से उड़ान भरी। इन हमलों में भारत ने पाकिस्तान के सिंध में एक हैंगर सहित महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया। बताया जा रहा है कि इन सटीक हमलों में पाकिस्तान ने अपने कई यूएवी और एक एयर सर्विलांस प्लेन के अलावा कई महत्वपूर्ण उपकरण खो दिए। भारत की ओर से हमले इतने जोरदार थे कि पाकिस्तानी वायु सेना को नुकसान के कारण अपने विमानों को पीछे के ठिकानों पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह ऑपरेशन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान की देखरेख में हुआ।

एनएसए डोभाल की सलाह पर ब्रह्मोस मिसाइल को मुख्य हथियार के रूप में चुना गया। ब्रह्मोस का इस्तेमाल भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं का एक मजबूत संकेत है। ब्रह्मोस एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इस भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। यह अपनी गति और सटीकता के लिए जानी जाती है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है।

यह लगभग मैक 3 की गति (ध्वनि की स्पीड से तीन गुना के आसपास) तक पहुंच सकती है और पूर्ण सटीकता के साथ 290 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को बर्बाद कर सकती है।

इसकी टू-स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम, स्टील्थ फीचर्स और एडवांस गाइडेंस टेक्नोलॉजी इसका पता लगाने और इसे रोकना बहुत ही मुश्किल बना देती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल 300 किलोग्राम तक का पारंपरिक वारहेड ले जा सकती है और मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर 15 किलोमीटर तक ऊंची या 10 मीटर तक नीची उड़ान भर सकती है।

पहला कॉलम

बीजेपी अपने फूट, चूक और लूट के लिए जानी जाएगी- अखिलेश

-सपा प्रमुख ने सीजफायर पर जश्न मनाने को लेकर उठाया सवाल

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पाकिस्तान के साथ सीजफायर पर जश्न मनाने को लेकर सवाल उठाया। इसके बाद बीजेपी ने अखिलेश की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। भारत-पाक के बीच सीजफायर चल रहा है। अखिलेश ने एक दिन पहले कहा था कि आखिरकार हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित क्यों नहीं हैं? कोई भी हमारी सीमा में घुस न पाए। सरकार को जनता को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि अब कभी हमला नहीं होगा। भाजपाई पूरी तरह से झूठ का भंडार है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अपने फूट, चूक और लूट के लिए जानी जाएगी। यही एक भाजपाई लोग हजारों किलोमीटर तिरंगे के लिए चले थे। अब कुछ किलोमीटर भी तिरंगा के लिए नहीं चल पा रहे हैं। जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। बता दें पहलगाम हमले के बाद से भारत-पाक की स्थिति तनावपूर्ण है। अखिलेश ने कहा कि सरकार अपनी सीमाओं को इतना मजबूत क्यों नहीं कर देती कि अगली बार चूक की कोई गुंजाइश ना हो। सरकार कह रही है कि अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या यह सरकार फिर हमले की तैयारी कर रही है? उन्होंने कहा कि जनता जागरूक और समझदार है। इस बार सबक सिखाएगी जो इनकी चूक हुई है, इस बार चुनाव हराएगी और बीजेपी के लोग बचने वाले नहीं हैं।

अब तो राहुल के करीबी सहयोगी भी जानते हैं कि पार्टी का कोई भविष्य नहीं

-बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भंडारी ने एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस पर कसा तंज

नई दिल्ली।

बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दल पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के करीबी सहयोगी भी जानते हैं कि पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। बता दें चिदंबरम ने इंडिया गठबंधन को लेकर चिंता जताते हुए गुरुवार को कहा था कि वह आश्वस्त नहीं हैं कि यह विपक्षी गठबंधन अब भी एकजुट है। चिदंबरम के बयान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पूर्वानुमान जताया है कि भविष्य में विपक्ष एकजुट नहीं रहेगा। बीजेपी मजबूत संगठन है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के करीबी सहयोगी चिदंबरम भी जानते हैं कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। चिदंबरम ने सलमान खुर्शीद और मृत्युंजय सिंह यादव की किताब के विमोचन के मौके पर कहा कि इंडिया गठबंधन का भविष्य उतना उज्ज्वल नहीं है, जैसा मृत्युंजय सिंह यादव ने कहा। उन्हें लगता है कि गठबंधन अब भी बरकरार है, लेकिन इसे लेकर मैं आश्वस्त नहीं हूं। केवल सलमान खुर्शीद इस पर जवाब दे सकते हैं क्योंकि वह इंडिया गठबंधन के लिए बातचीत करने वाली टीम का हिस्सा थे। चिदंबरम ने कहा कि अगर गठबंधन पूरी तरह से कायम है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि यह कमजोर पड़ गया है। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि गठबंधन अब भी कायम रह सकता है, अब भी समय है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के मुताबिक इंडिया गठबंधन एक ऐसे मजबूत तंत्र के खिलाफ लड़ रहा है, जिससे सभी मोर्चों पर लड़ा जाना चाहिए। गत वर्ष लोकसभा चुनाव में एनडीए से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठगंधन बनाया था।

'ऑपरेशन सिंदूर' खतरे की वह लाल लकीर है, जो भारत ने आतंकवाद के माथे पर खींच दी : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

भुज।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज एयर बेस से भारतीय वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को एक बार फिर चेताया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ, वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब सही समय आएगा, हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को सफलता की बधाई देते हुए कहा कि मैं बस इतना कहूंगा कि आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया कि यह वो सिंदूर है, जो श्रृंगार का नहीं, बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वो सिंदूर है, जो सौंदर्य का नहीं, बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर, खतरे की वह लाल लकीर है, जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। मैं इस अवसर पर, आप सभी के साथ-साथ, देश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। भारत की जनता ने, एकजुटता और समझदारी का परिचय देते हुए, आपका सहयोग किया। इस लड़ाई में न केवल सरकार, आर्म्ड फोर्सेज और सुरक्षाबल एकजुट थे, बल्कि भारत का हर नागरिक, एक सिपाही की तरह इसमें भागीदार बना। उन्होंने कहा कि हम, हमारे आराध्य श्रीराम के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें वह आसुरी शक्तियों के विनाश का प्रण लेते हैं। 'निसिचर हीन करउँ महि, भुज उठाइ पन कीन्ह।' अर्थात जिस प्रकार भगवान राम ने, अपनी भुजाओं को उठाकर, धरती को राक्षस विहीन करने का प्रण लिया था। ठीक उसी प्रकार, प्रभु श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए, हमने भी आतंकवाद को, जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आपने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है लेकिन, पाकिस्तान इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम लोगों से लिया गया टैक्स जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी जैसे मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी। जबकि वह यूएन से आतंकी घोषित हो चुका है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा अपने देश में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर खर्च करेगा, ऐसा मेरा मानना है। भारत चाहता है कि आईएमएफ पाकिस्तान को दिए जाने वाले वित्त पोषण पर पुनर्विचार करे, और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे। उन्होंने कहा कि आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व पैदा होता है, जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है, तो उसे उचित दंड दिया जाता है। ठीक उसी तरह, वर्तमान सीजफायर में, हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है, तब तो ठीक और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है, तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, पाकिस्तान को हमने प्रोबेशन पर रखा है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक पर प्रहार अब न्यू नॉर्मल है। ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है।

भारत ने तुर्की की हर तरह मदद की, इसके बाद भी गद्दारी कर पाक का देने लगा साथ

नई दिल्ली। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नापाक हरकत में पाकिस्तान का साथ देने के लिए उसका एक ऐसा 'दोस्त' आगे आया, जिसने भारत के सारे एहसानों को पल भर में भुला दिया। यह 'दोस्त' और कोई नहीं तुर्की था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। जिस देश ने कभी मुश्किल समय में भारत से मदद ली थी उसी ने आज हमारी सेना और आम लोगों को निशाना बनाने के लिए पड़ोसी मुल्क को ड्रोन और हथियार सप्लाई किए। तुर्की ने दोस्ती की सारी हदें पार कर दीं और साबित कर दिया कि उसके लिए भारत के साथ निभाए गए पुराने रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। अब भारत में इस धोखे का जबरदस्त विरोध हो रहा है और हर भारतीय के मन में यही सवाल है कि क्या दोस्ती का यही सिला मिलता है?

भूकंप में भारत ने की थी खास मदद

फरवरी 2023 में तुर्की में आए बेहद भयंकर और महाविनाशकारी भूकंप में भारत मदद करने वाले पहले देशों में से एक था। इस दौरान भारत की ओर से 'ऑपरेशन दोस्त' चलाकर तुर्की के लोगों की मदद की थी। 'ऑपरेशन दोस्त' के तहत भारत ने तुर्की में जाकर न केवल लोगों को बचाया था बल्कि बड़ी तादाद में राहत सामग्री भी भेजी थी। इसके लिए भारतीय वायुसेना के सी-17 ग्लोबमास्टर विमान का भी उपयोग किया गया था। वहीं अब तुर्की की एहसान फरामोशी का जवाब देने भारत की जनता खुद सामने आ गई है और खुलकर तुर्की के उत्पादों का बायकॉट कर रही है।

तुर्की के सेबों का बायकॉट किया

गाजियाबाद के साहिबाबाद के फल विक्रेताओं ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए हमने तुर्की के सेबों का बायकॉट करने का फैसला लिया है। फल विक्रेताओं ने आगे कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों से हम व्यापार नहीं करेंगे। वहां से अब सेब के साथ किसी अन्य फल का भी आयात नहीं किया जाएगा। अब हमने हिमाचल या फिर किसी अन्य भारतीय राज्य से सेब खरीदने का फैसला किया है। आमतौर पर भारत में तुर्की से हर साल 1,000 से 1,200 करोड़ रुपए के सेब आयात किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने के कारण मार्बल उद्योग ने भी आयात को बायकॉट करने का फैसला किया है। इससे तुर्की को काफी आर्थिक चोट पहुंच सकती है।

तुर्की बायकॉट ट्रेंड कर रहा है

इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी तुर्की बायकॉट ट्रेंड कर रहा है और लोग तुर्की घूमने की अपनी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का मन बना चुके हैं। इस कारण से बड़ी संख्या में भारत से तुर्की जाने की बुकिंग रद्द हो रही हैं। भारत के शीर्ष उद्योग निकाय कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सभी व्यापारियों और नागरिकों से तुर्की और अजरबैजान का बायकॉट करने की अपील की। 2024 में तुर्की में करीब 62.2 मिलियन विदेशी यात्री आए थे। इसमें से 3,00,000 के आसपास भारतीय थे।

सपा का रवैया राष्ट्रहित के खिलाफ है, वह जातिगत जहर फैलाने का कर रही प्रयास

-बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी पर देश विरोधी और जातिवादी बयानों के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सपा का रवैया न केवल राष्ट्रहित के खिलाफ है, बल्कि यह समाज को बांटने और जातिगत जहर फैलाने का भी प्रयास कर रही है। भाटिया ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के अपमान का मुद्दा उठाते हुए सपा नेतृत्व से जवाब मांगा और रामगोपाल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। भाटिया ने कहा कि पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है, लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लगातार देश विरोधी बयानबाजी और अब जातिगत टिप्पणियों में लिप्त है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव को हमारी बहन, विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नाम तक नहीं पता। वे उन्हें दिव्या सिंह कह रहे हैं। यह हमारी सेना और उसकी वीरांगना का अपमान है। सेना का कोई धर्म या जाति नहीं होती, केवल एक धर्म होता है और वह है भारत। फिर भी सपा बार-बार जाति की बात उठाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है।

भाटिया ने कहा कि क्या अखिलेश यादव रामगोपाल यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सपा की मानसिकता ही देश विरोधी और समाज को तोड़ने वाली है।

सपा का यह रवैया इसलिए है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति करे। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी तंज कसा। भाटिया ने कहा कि यह गठबंधन वास्तव में एक ठगबंधन था, जो भारत विरोधी मानसिकता की प्रयोगशाला में तैयार हुआ था। इसका एकमात्र उद्देश्य पीएम मोदी को गाली देना और देश को कमजोर करना था। इसमें न नीति थी, न नेतृत्व, न ही देशहित का कोई विजन।

उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक के विधायक मंजुना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाने को सेना के शौर्य का अपमान बताया। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं को भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है। यह उनकी देश विरोधी मुहिम का हिस्सा है। भाटिया ने विपक्ष से अपील की कि वे अपना भारत विरोधी चश्मा उतारें और समाज को बांटने वाली राजनीति छोड़ें। उन्होंने कहा विपक्ष के नेताओं को इस तरह के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा जनता इसका जवाब देगी।

वजय शाह विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब 19 मई को

नई दिल्ली।

मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 मई निर्धारित की है। यह मामला अब न्यायिक रूप से और गंभीर होता जा रहा है। मंत्री विजय शाह ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाली सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर देशभर में आक्रोश देखने को मिला। मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 19 मई 2025 तक मामले को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने याचिका की प्राथमिक सुनवाई के बाद अगली तिथि निर्धारित की, लेकिन कोई अंतरिम राहत या आदेश पारित नहीं किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर रुख अपनाया हुआ है और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। अब 19 मई को सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि हाईकोर्ट का एफआईआर दर्ज करने का आदेश स्थगित किया जाए या बनाम सुनवाई जारी रखी जाए।

एमपीएमएसयू का नया कारनामा, प्रश्नपत्र रद्द करने उठ रही मांग

नर्सिंग के पर्चे में पूछ लिया बेतूका सवाल!

जबलपुर।

अपने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को एक उचित कारण देते हुए परीक्षा तिथी बढ़ाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। नर्सिंग के गुरुवार को हुए प्रश्न पत्र में मप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (एमपीएमएसयू) प्रबंधन द्वारा पूछे गए इस सवाल से प्रदेश भर में बवाल मच गया हैं। नर्सिंग विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को पाठ्यक्रम से बाहर का सवाल बताते हुए समूचा प्रश्न पत्र रद्द करने की मांग की हैं। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री और अन्य जिम्मेदारों से भी शिकायत की जा रही हैं।

इतना गिर चुका हैं स्तर.....

नर्सिंग विद्यार्थियों का आरोप हैं कि इस तरह का प्रश्न यदि स्कूली स्तर के विद्यार्थियों पूछा गया होता तो बात समझ भी आती हैं लेकिन एमपीएमएसयू द्वारा इस तरह का सवाल नर्सिंग जैसे गंभीर विषय के प्रश्न पत्र में पूछा जाना न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि यह प्रश्न अपने आप में बताने काफी हैं कि विश्वविद्यालय का स्तर कितना गिर चुका हैं। नर्सिंग विद्यार्थियों का आरोप हैं कि इस सवाल के विकल्प में एक तरफ तो यह पूछा गया कि किसी नर्स को किसी वार्ड की रिकार्ड रिपोर्टिंग करते वक्त किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। परीक्षार्थियों ने कहा कि यह सवाल नर्सिंग से जुड़ा होने की वजह से जवाब देने योग्य भी हैं लेकिन अरसे बाद विद्यार्थियों की मांग पर किसी तरह परीक्षाएं होने पर परीक्षा तिथी बढ़ाने आवेदन विद्यार्थियों को कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत हुआ जैसे विश्वविद्यालय प्रबंधन उनका मखौल उड़ा रहा हो। इस संबंध में एमपीएमएसयू के वीसी अशोक खंडेलवाल एवं कुलसचिव डॉ. पुष्पेंद्र सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया)

एपीवाई में महिलाओं की भागीदारी में तेजी से हो रहा इजाफा

अटल पेंशन योजना के 7.65 करोड़ हुए सब्सक्राइबर्स, 48 फीसदी महिलाएं

नई दिल्ली।

अटल पेंशन योजना के 7.65 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से 48 फीसदी महिलाएं हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया है कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को मई 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन का एक अच्छा और विश्वसनीय विकल्प देना था, जिससे रिटायरमेंट के बाद वे अपनी जिंदगी आराम से जी सकें। एपीवाई में पेंशन योजना में शामिल होने की आयु और अंशदान की राशि के आधार पर निर्भर करती है। इसका लक्ष्य मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के गरीब और वंचित श्रमिकों को पहुंचाना था और यह भारत में सबसे समावेशी और सुलभ सामाजिक सुरक्षा पहलों में उभरा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समाज कल्याण विभाग ने कहा कि अप्रैल 2025 तक एपीवाई से 7.65 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, जिससे कुल 45,974.67 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित हुई है। एपीवाई में महिलाओं की भागीदारी में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब कुल सब्सक्राइबर्स में महिलाओं का शेयर 48 फीसदी हो गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में जुड़े नए सब्सक्राइबर्स में से 55 फीसदी से ज्यादा महिलाएं थीं। एपीवाई योजना शुरू में 18 से 40 साल की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध थी। अक्टूबर 2022 से आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत सब्सक्राइबर्स को उनके अंशदान के आधार पर 60 साल की आयु में एक निश्चित मासिक पेंशन (1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपए प्रति माह) प्रदान की जाती है।

विभाग ने कहा कि अटल पेंशन योजना खासतौर पर भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा इकोसिस्टम की आधारशिला बनकर उभरी है। करीब 7.65 करोड़ ग्राहकों और लगातार बढ़ती पेंशन राशि के साथ, यह योजना न केवल बुजुर्गों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता तय करती है,

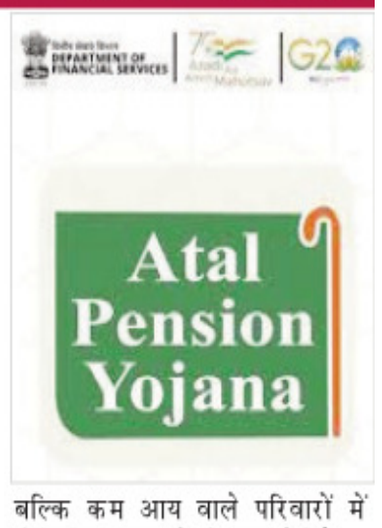

बल्कि कम आय वाले परिवारों में दीर्घकालिक बचत को भी बढ़ावा देती है।

भारत के रक्षा बजट में होगा 50 हजार करोड़ का इजाफा, और ताकतवर होगी सेना

नई दिल्ली।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखते हुए मोदी सरकार अपना खजाना खोलने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत के रक्षा बजट में 50 हजार करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है।

रिपोर्ट्स की मानें तो 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए सरकार रक्षा बजट में अलग से 50,000 करोड़ रुपये का इजाफा कर सकती है। इसका प्रस्ताव तैयार है। अगर सरकार ने इस अतिरिक्त रकम को मंजूरी दे दी, तो वित्त वर्ष 2025-26 में कुल रक्षा बजट सात लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगा।

दरअसल, 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने रक्षा को केंद्र बिंदु बनाया है। अपने पहले साल में मोदी सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 2.29 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जो पिछले एक दशक में तीन गुना से भी ज्यादा है। इस बार भारत के कुल बजट का 13 प्रतिशत हिस्सा रक्षा को आवंटित किया गया है। यह सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है।पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच सैन्य तैयारियों पर यह जोर दिया जा रहा है।

खास तौर पर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत की 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत की गई सैन्य कार्रवाई के बाद। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था।

1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही सशस्त्र बलों के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया था। यह 2024-25 में आवंटित 6.22 लाख करोड़ रुपये से 9.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। सूत्रों का कहना है कि इस 50 हजार करोड़ वाली राशि का इस्तेमाल डिफेंस रिसर्च यानी रक्षा अनुसंधान और हथियारों, गोला-बारूद और अन्य अहम सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। साथ ही सेना की अन्य जरूरतों को पूरा करने में भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा।

माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 50 हजार करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी जा सकती है।

आखिरकर क्यों भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा ऑपरेशन सिंदूर

पीएम मोदी ने बता दी इसकी वजह

नई दिल्ली।

भारत ने 6 और 7 मई की रात के दरमियान एक ऐतिहासिक और साहसिक सैन्य कार्रवाई कर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जो भविष्य में आतंकवाद और सैन्य रणनीति की पढ़ाई में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह पहली बार है जब भारत ने परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के भीतर जाकर इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को कहा कि यह ऑपरेशन सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति की घोषणा थी। उन्होंने बताया कि भारतीय ड्रोन और मिसाइलों ने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की ओर से की गई परमाणु हमले की धमकियों को दरकिनार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 10 मई को भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के रणनीतिक ठिकानों-रावलपिंडी, चकलाला और सरगोधा एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को प्रत्यक्ष चेतावनी दी गई। भारतीय वायुसेना के हमलों में पाकिस्तान को सैन्य और मनोवैज्ञानिक दोनों मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। पीएम मोदी ने दो टूक कहा, भारत अब आतंक के सौदागरों को उन्हीं की जमीन पर ही जवाब देगा। पाकिस्तान ने सीमा पर हमला करने की तैयारी की थी, लेकिन भारत ने उसके दिल पर हमला किया। सैन्य सूत्रों के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तानी वायुसेना को अपने ठिकाने पीछे खींचने पड़े। यह ऑपरेशन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह दिखाता है कि अब भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरता और सटीक जवाब देने को तैयार है।

भारत-पाकिस्तान तनाव कम करने पर सहमत, दोनों चाहते हैं सीमा पर शांति हो

सहमति के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और बातचीत के खुल सकते हैं रास्ते

नई दिल्ली।

भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय सेना ने गुरुवार को जानकारी दी कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 10 मई को हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने सीमा पर तनाव कम करने और सतर्कता के स्तर को घटाने के उपाय जारी रखने पर सहमति जताई है। यह फैसला दोनों देशों के लिए अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह दोनों पक्षों के बीच विश्वास निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम है। बता दें 10 मई को भारतीय और पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने सीमा पर तनाव कम करने और सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की। भारतीय सेना द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने विश्वास निर्माण उपायों को जारी रखने का फैसला लिया, जिससे सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान को एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करने से बचना चाहिए और एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए यह प्रतिबद्धता भी दोनों देशों के बीच साझा की गई। दोनों सेनाओं ने यह भी तय किया कि सीमा और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी की जाएगी, ताकि स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सके। पिछली बार 12 मई को डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें संघर्ष विराम समझौते को कायम रखने पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम का समझौता बड़े हद तक कायम है, हालांकि कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन देखे जाने की घटनाएं सामने आईं। इसके बावजूद दोनों सेनाओं ने एक-दूसरे पर गोलीबारी की घटनाओं को कम करने और शांति बनाए रखने की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने सीमा पार करके और नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी करके इन समझौतों का उल्लंघन किया। यह घटनाएं शनिवार रात और रविवार तड़के पश्चिमी मोर्चे के विस्तार में ड्रोन घुसपैठ के रूप में सामने आईं। भारतीय सेना और सरकार ने साफ कहा है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। भारतीय सेना की ओर से यह भी कहा गया कि सीमा पर सैन्य तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों की सहमति जरूरी है और इस दिशा में किए गए कदम काफी अहम हैं। यह सहमति भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग और बातचीत के नए रास्ते खोल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन बेंगलुरु के पक्ष में सुनाया फैसला, मुंबई इस्कान को झटका

मुंबई।

मुंबई बनाम इस्कॉन बेंगलुरु विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन बेंगलुरु के पक्ष में फैसला दे दिया है। बेंगलुरु हरेकृष्ण हिल टेंपल इस्कॉन बेंगलुरु के पास ही रहेगा। मुंबई इस्कॉन के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को पलटकर फैसला सुनाया है और निचली अदालत के द्वारा सुनाए गए फैसले को अदालत ने सही ठहराया है। निचली अदालत ने इस्कॉन मुंबई के अधिकार को खारिज कर कहा था कि इस्कॉन बेंगलुरु इस्कॉन मुंबई की शाखा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र संस्था है। यह विवाद दशकों पुराना है, जिसका अब निपटारा हुआ है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया है। 15 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट में आए मामले में आठ साल बाद 24 जुलाई 2024 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। दरअसल, इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी के महासमाधि में जाने के बाद उनके शिष्यों के बीच सिद्धांतों को लेकर विवाद शुरू हुआ। इस्कॉन मुंबई पर ज्यादा प्रभाव प्रभुपाद के विदेशी शिष्यों का था। उन लोगों पर आरोप है कि समाधि प्रवेश से पहले प्रभुपाद की उस वसीयत का पालन नहीं किया गया, जिसमें भविष्य में इस्कॉन के संचालन की रूपरेखा थी। इसमें 12 साधुओं की प्रशासन समिति आयोग जैसी व्यवस्था थी। शिष्य परंपरा प्रभुपाद के गुरुनाम से ही संचालित रखने का सिर्फ एक विकल्प था, लेकिन आरोप है कि ये सभी 12 लोग अपनी मर्यादा से गिर गए।

साइबर ठगी का शिकार हुआ निवृत्त कर्मचारी, गंवाए 63.30 लाख रुपए

सूरत।

सूरत के बारडोली से साइबर ठगी की घटना सामने आई है, जिसमें एक निवृत्त कर्मचारी ने रु. 63.30 लाख रुपए गंवा दिए7 पूरा मामला तब सामने आया है कर्मचारी के बेटे को इसका पता चला और उसने अपने पिता को बगैर डरे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी7 जानकारी के मुताबिक सूरत जिले में बारडोली के चाणक्यपुरी निवासी निवृत कर्मचारी अजय चावडा को किसी अज्ञात मोबाइल नंबर से कोल आया, जिसमें कहा गया कि मुंबई में जेट एयरलाइंस में 680 करोड़ के फ्राड में आपके बैंक एकाउंट का उपयोग किया गया है7 इसलिए हम बैंक एकाउंट का ब्यौरा भेज रहे हैं, जिसमें बिना किसी विलंब के रकम जमा कराएं7 हांलाकि अजय चावडा ने इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी7 दूसरे दिन फिर अजय चावड़ा को वीडियो कोल आया7 जिसमें मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने का सेटअप दिख रहा था और तीन लोग वीडियो कोल में बात कर रहे थे7 तीन में एक व्यक्ति को खुद की पहचान सीबीआई अधिकारी और दूसरे ने न्यायधीश बताया7 सीबीआई और न्यायधीश का नाम सुनकर अजय चावड़ा घबरा गए7 वीडियो कोल कर रहे ठगों ने अजय चावड़ा से कहा कि आपके नाम अरेस्ट वारंट जारी हुआ है7 साथ ही आपके बैंक एकाउंट को फ्रीज करने का ऑर्डर भी आया है7 अब अदालत में मामले की सुनवाई होगी7 अगर आपको जमानत चाहिए तो हम जो बैंक एकाउंट का ब्यौरा भेज रहे हैं, उसमें जमानत के लिए तुरंत पैसे जमा करवाने होंगे7 इसके बाद ठगों ने अजय चावड़ा को विभिन्न बैंकों के पांच एकाउंट का ब्यौरा भेज दिया7 पकड़े जाने के डर से अजय चावड़ा ने आरटीजीएस के जरिए करीब रु. 61.30 लाख उन्हें बताए गए बैंक एकाउंट में जमा करवा दिए7 जिसके बाद ज्यादा रकम ऐंठने की लालच में साइबर ठग अजय चावडा को कोल कर धमकाने लगे7 एक दिन अजय चावड़ा का बेटा अपने पिता को फोन पर बात करते सुन गया और तब पूरा मामला सामने आया है7 इसके बाद बेटे ने अपने पिता को हिम्मत दी और कहा कि वे बगैर किसी विलंब के तुरंत पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं7 अजय चावडा की शिकायत पर बारडोली शहर पुलिस ने आईटी एक्ट और बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है7

मौके का फायदा उठाने के लिए चीन सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय

तीन राज्यों में सेना का हाई अलर्ट

मणिपुर।

पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और हमले के कारण चीन ने अपनी गतिविधियां सीमावर्ती भारतीय राज्यों में बढ़ा दी हैं। भारत की पूर्वी सीमा पर उत्तर पूर्वी बॉर्डर पर चीन की गतिविधियां बढ़ने से भारतीय सेना चिंतित है। चीन के द्वारा म्यांमार के रास्ते बड़ी संख्या में उग्रवादियों को भारत भेजा जा रहा है। मणिपुर में सेना के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार उन्हें इनपुट मिला है। चीन भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही जंग के बीच तीन राज्यों में घुसपैठ कराकर भारत के लिए चुनौती पैदा कर रहा है। म्यांमार के रास्ते से बड़ी संख्या में घुसपैठिया भारत में प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय सेना ने इसकी रोकथाम के लिए 4000 अतिरिक्त सैनिकों को सीमा क्षेत्र में तैनात किया है। भारतीय सेना द्वारा जगह-जगह तलाशी का अभियान चलाया गया है। चीन और बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्यों में घुसपैठ को रोकने के लिए रेलवे पुलिस, बीएसएफ एवं अन्य सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। एक विदेशी ड्रोन दुर्गापुर बार्डर के गांव में भी मिला है। यहां से बीएसएफ ने 17 बांग्लादेशी को भारतीय सीमा में घुसते हुए पकड़ा था। इसमें उग्रवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के दो सदस्य थे।

अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ बढी हैं। चीन भारतीय गांवों के नाम बदलने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल के आसपास सड़कों का निर्माण और नए मिलिट्री कैंप चीन द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय सेना इस पर भी निगाह रख रही है। भारतीय सेना के अधिकारियों का मानना है। चीन भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति के तहत भारत की सीमावर्ती राज्यों में अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है। जिसके कारण सेना की चुनौतियां बढ़ गई हैं।

सीएम योगी ने मेरा पूरा बयान सुने बगैर ही अपनी प्रतिक्रिया दे दी

व्योमिका सिंह पर विवादित बयान देने के बाद रामगोपाल ने दी सफाई

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित बयान देने के बाद उनकी हर तरफ आलोचना हो रही थी। अब इस मामले में उन्होंने सफाई दी है। राम गोपाल ने इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा कि सीएम ने पूरा बयान सुने बिना ही अपनी प्रतिक्रिया दे डाली।

रामगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- उत्तर भारत के कुछ राज्यों में विशेषकर यूपी में जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हों, एनकाउंटर किए जा रहे हों, गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हों, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिया, इसलिए गाली दी गई। विदेश सचिव मिस्त्री को गाली दी गई। अगर इन गालीबाजों को ये पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं तो ये इन अफसरों को भी गालियाँ देने से बाज नहीं आते।

रामगोपाला यादव ने आगे लिखा कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हों उन्होंने मेरा पूरा बयान सुने बगैर ही ट्वीट कर दिया, जिन मीडिया चैनलों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया था। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन पर सत्ता पक्ष के अलावा किसी को विश्वास नहीं।

बता दें रामगोपाल द्वारा गुरुवार को विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर की गई जातिसूचक टिप्पणी पर सीएम योगी ने एक्स हैंडल पर रामगोपाल यादव के खिलाफ प्रतिक्रिया में कहा था कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्रधर्म निभाता है, न कि

किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। यह वही मानसिकता है, जो तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है।

गेमिंग वेबसाइट के विज्ञापन के झांसे में गंवाए 1.9 लाख रुपये

नई दिल्ली।

23 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट युवती ने इंस्टाग्राम पर दिखे एक गेमिंग वेबसाइट के विज्ञापन के झांसे में आकर 1.9 लाख रुपये गंवा दिए। गेमिंग वेबसाइट के विज्ञापन में कुछ सेकेंड में पैसे डबल होने का दावा किया गया था, जिसने पीड़ित को लालच में डाल दिया। जैसे ही उसने लिंक पर क्लिक किया, एक आकर्षक वेबसाइट खुली जो पूरी तरह असली जैसी दिख रही थी। इसमें निवेश पर बोनस और त्वरित इनाम का वादा किया गया था, जिससे भरोसा बना और फिजियोथेरेपिस्ट ने शुरुआत में 101 रुपये जमा किए। बोनस मिलने का भ्रम होते ही उसने दो हफ्तों में बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दी। 18 अप्रैल से 5 मई के बीच उसने 1.9 लाख रुपये डिपॉजिट कर दिए। जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की, तब असलियत सामने आई वेबसाइट पर विड्रॉ का ऑप्शन ही डिसेबल था। इसके बावजूद वेबसाइट ने बार-बार उसे और निवेश करने के लिए उकसाया। जब भी पैसे निकालने का प्रयास किया गया, नई डिपॉजिट की मांग की जाती रही। पीड़ित ने सभी संभव कोशिशें कीं, लेकिन वह अपनी रकम वापस नहीं ले सका। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे फर्जी प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को असली गेमिंग वेबसाइट का भ्रम देकर ठगते हैं। किसी भी अज्ञात वेबसाइट पर अपने बैंक या यूपीआई डीटेल्स शेयर करने से बचें और हमेशा अधिकृत ऐप्स व वेबसाइट्स का ही उपयोग करें। अगर किसी तरह की ऑनलाइन ठगी हो जाती है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस थाने या साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) पर संपर्क करें। इन मामलों से बचने के लिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है। कभी भी इंस्टाग्राम या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले पैसे डबल करने वाले विज्ञापनों पर भरोसा न करें।

संक्षिप्त समाचार

डीवाई चंद्रचूड़ बने,नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ नेशनल लॉ कॉलेज में अब छात्रों को पढ़ाएंगे। उन्होंने सेवा निवृत्ति के बाद प्रोफेसर के रूप में नेशनल लॉ कॉलेज में पढाने का निर्णय लिया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा, देश में कानूनी शिक्षा के लिए उनका छात्रों को पढाना एक परिवर्तनकारी स्थिति है। इसका लाभ ला के छात्रों को मिलेगा। डीवाई चंद्रचूड़ एक प्रोफेसर के रूप में अपने अनुभव का लाभ ला के विद्यार्थियों को देंगे। सेवा निवृत्ति के समय उन्होंने चिंता प्रकट की थी। उनके मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को किस तरीके से देखा जाएगा। निश्चित रूप से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने जो मार्ग चुना है। इसका लाभ कानून के विद्यार्थियों को मिलेगा।

एसएससी भर्ती मामला:शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस से झड़प में कई घायल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती मामले में सीएम ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने विकास भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है। गुरुवार रात, विकास भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे एसएससी शिक्षकों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई जिसके बाद पुलिस ने भारी भीड़ को तितर-बितर करने लाठीचार्ज किया जिसमें कई शिक्षक घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेरोजगार हुए शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने गुरुवार को साल्ट लेक में राज्य शिक्षा विभाग के मुख्यालय की घेराबंदी करने के लिए रेलिंग के घेरे को तोड़ दिया और लोहे के गेट तोड़ दिए। उन्होंने विकास भवन के सैकड़ों कर्मचारियों को 8 घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाए रखा, जब तक कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए रात 8 बजे से बल प्रयोग करना शुरू नहीं कर दिया। कई प्रदर्शनकारियों को खून से लथपथ देखा गया और उन्होंने शिकायत की कि पुलिस ने उन्हें डंडों से मारा, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने सुबह से ही उल्लेखनीय ÷संयम÷ दिखाया और सबसे पहले उन पर ईंटों से हमला किया गया। हालांकि कुछ बंधकों को समूहों में निकाल लिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के वापस लौटने के कारण कई लोग इमारत में ही फंस गए। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे विकास भवन के सामने एक सामूहिक सम्मेलन की घोषणा की। कुछ आंदोलनकारी अभी भी परिसर के अंदर थे। पुलिस तैनात है।

शादी में सजावट कर लौट रहे माली की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार

पटना। पटना में गुरुवार देर रात एक माली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक बाजितपुर गांव का रहने वाला राकेश कुमार (22) है। पुलिस के मुताबिक राकेश एक शादी समारोह से सजावट का काम करके घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव के मंदिर के पास कुणाल सिंह ने उसे गोली मार दी। दोनों में पुरानी रंजिश थी। घायल हालत में परिजन राकेश को निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बिहटा थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पटना एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। बताया जा रहा है मृतक राकेश कुमार का एक बच्चा है और पत्नी गर्भवती है। हत्या के बाद से आरोपी कुणाल सिंह फरार है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।

एएसआई ने जब्त वाहन छोड़ने मांगी रिश्वत, निगरानी विभाग ने रंगे हाथ पकड़ा

पटना।

दानापुर के रूपसपुर थाने में तैनात एएसआई ब्रजेश कुमार को निगरानी विभाग ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एएसआई ने थाने में जब्त वाहन छोड़ने के बदले में 22 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बीबीगंज निवासी बासु कुमार ने 15 मई को इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने एएसआई ब्रजेश कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी विभाग ने कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक निगरानी टीम ने रूपसपुर थाना क्षेत्र के राम जयपाल नगर से एएसआई को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। रूपसपुर थाना प्रभारी ने बताया कि 14 अप्रैल को नगर रोड पर एक मिक्सचर मशीन और ऑल्टो कार की टक्कर हो गई थी। हादसे में ऑल्टो का चालक घायल हो गया था। उसे पटना एम्स में भर्ती कराया था। पुलिस ने ऑल्टो से 20 लीटर अवैध शराब बरामद की थी। दोनों वाहनों को जब्त कर लिया था। थानाध्यक्ष ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किस वाहन को छोड़ने के लिए एएसआई ने रिश्वत मांगी है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717